

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. निगरानी संख्या - 2201 / 2007 / जोधपुर.
2. निगरानी संख्या - 2203 / 2007 / जोधपुर.

विश्वकर्मा स्टोन क्राफ्ट प्रा0 लिमिटेड,
जरिये निदेशक चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा धनरेवा,
निवासी मीरा सदन बागर चौक, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर.प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, लूणी, जोधपुर.
2. जवाहरलाल पुत्र श्री सोहनलाल
3. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री जवाहरलाल
4. श्रीमती वसूदा पत्नी श्री सूरतिशील पुत्री श्री जवाहरलाल
निवासी शकुन निवास, ई-13, शास्त्रीनगर, जोधपुर.अप्रार्थीगण.

3. निगरानी संख्या - 2202 / 2007 / जोधपुर.

विश्वकर्मा स्टोन क्राफ्ट प्रा0 लिमिटेड,
जरिये निदेशक चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा धनरेवा,
निवासी मीरा सदन बागर चौक, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर.प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, लूणी, जोधपुर.
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति जैन
3. श्रीमती शांतादेवी पत्नी श्री मोहनलाल जाति जैन
निवासीगण मकान नं0 92 नेहरू पार्क, जोधपुर.अप्रार्थीगण.

4. निगरानी संख्या - 2204 / 2007 / जोधपुर.

विश्वकर्मा स्टोन क्राफ्ट प्रा0 लिमिटेड,
जरिये निदेशक चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र श्री भागीरथ शर्मा धनरेवा,
निवासी मीरा सदन बागर चौक, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर.प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, लूणी, जोधपुर.
2. हीरालाल पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र जाति सिंधी गंगवाणी
निवासी म.नं. बी-21, कमलानेहरू विस्तार योजना, जोधपुर.अप्रार्थीगण.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री गौरव दवे, अभिभाषकप्रार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषकअप्रार्थी संख्या 1 की ओर से.

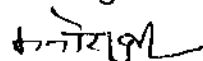
.....

.....अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31 / 10 / 2014

निर्णय

1. ये चारों निगरानियां प्रार्थी मैसर्स विश्वकर्मा स्टोन्स क्राफ्ट प्रा0 लिमिटेड, जोधपुर द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), जोधपुर (जिसे आगे 'कलेक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या क्रमशः 11/05; 12/05; 26/05 एवं 27/05 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 28.12.2006 एवं उक्त आदेशों में राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा)



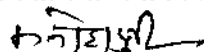
लगातार.....2

की धारा 52 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्रों में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 29.8.2007 के विरुद्ध मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन चारों निगरानियों में विवाद बिन्दु समान होने से सभी का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 द्वारा ग्राम मौंगड़ा कलां, लूणी, जोधपुर के खसरा नम्बर 111/1 व 111/6 की अपने स्वामित्व की कृषि भूमि क्रमशः 3 बीघा, 2 बीघा, 2 बीघा व 2 बीघा का विक्रय प्रार्थी को करना दर्शाते हुए निष्पादित दस्तावेज पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 उप पंजीयक, लूणी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उप पंजीयक द्वारा बिक्रीत सम्पत्तियों की मालियत, दस्तावेजों में दर्शाये अनुसार मानते हुए तदनुसार मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल की जाकर दस्तावेज पंजीबद्ध कर पक्षकारों को लौटा दिये गये। तत्पश्चात महालेखाकार जांचदल द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज कमी मालियत पर पंजीबद्ध होना आक्षेपित करते हुए, बिक्रीत सम्पत्तियों की मालियत क्रमशः रुपये 4,86,000/-; रुपये 9,72,000/-; रुपये 4,86,000/- व रुपये 9,72,000/- मानी गयी। उक्त आक्षेपों की पालना में उप-पंजीयक द्वारा उपरोक्तानुसार मालियत प्रस्तावित करते हुए मुद्रांक अधिनियम की धारा 53(5) के तहत रेफरेंस कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किये। कलेक्टर (मुद्रांक) ने पृथक-पृथक पारित किये गये निगरानी अधीन आदेश दिनांक 28.12.2006 सपठित आदेश दिनांक 29.8.2007 से रेफरेंस स्वीकार करते हुए प्रार्थी से कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति सहित क्रमशः रुपये 33,760/-; रुपये 80,460/-; रुपये 33,760/- व रुपये 80,460/- वसूल किये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा ये निगरानियां प्रस्तुत की गयी हैं।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

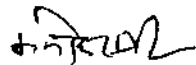
4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ना तो प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है एवं ना ही सम्पत्ति के विक्रेता (अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4) को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों की पालना किये बगैर निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानियां स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।



5. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेशों का समर्थन करते हुए प्रार्थी की निगरानियां अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।
7. प्रकरणों में कलेक्टर (मुद्रांक) की पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रश्नगत सम्पत्तियों का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया गया है तथा बिक्रीत सम्पत्ति के विक्रेतागण (अप्रार्थी संख्या 2) को भी सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(3) के अनुसार कलेक्टर (मुद्रांक) को किसी भी दस्तावेज की मालियत के निर्धारण से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना एवं राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 अनुसार सम्पत्ति का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।
8. इस सम्बन्ध में मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(3) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

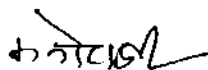
51. Instruments under valued, how to be valued -

- (1)
 - (2)
 - (3) On receipt of the instrument under sub-section (1) or (2) the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in the prescribed manner, determine the market Value and duty including the penalty not exceeding ten times the deficient stamp duty chargeable and surcharge, if any, payable thereon and if the amount of duty including penalty and surcharge, if any, so determined exceeds the amount of duty including penalty and surcharge, if already paid, the deficient amount shall be payable by the person liable to pay the duty including penalty and surcharge, if any.
9. इसी प्रकार राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 का नियम 65 निम्नानुसार है :-



65. Procedure to be followed by the Collector in cases of under valued instruments.-

- (1) On receipt of a reference under sub section (1) or sub section (2) of section 51 of the Act from the Registering officer, the Collector shall issue a notice to the person liable to pay the duty informing him of the receipt of the reference and asking to show that market value of the property has been truly setforth in the instrument and also produce all evidence that he has in support of his representation, within 21 days from the date of service of the notice.
- (2) On receipt of a reference under sub-section (4) of section 51 of the Act or where the Collector proposed to take action suo-moto under sub-section (5) of section 51 of the Act, the Collector shall issue a notice—
 - (a) to every person by whom; and
 - (b) to every person in whose favour, the instrument has been executed;asking them to produce the original instrument and to show cause within 21 days from the service of the notice as to why he should not proceed to determine the correct market value of the property and realise the deficient duty together with penalty under section 51 of the Act, where the original instrument is not produced within the above period of 21 days, the Collector may proceed to determine the correct market value on the copy of the instrument.
- (3) After expiry of 21 days from the service of notice, Collector shall summarily examine the matter, and if he thinks fit may record a statement of any person to whom a notice under sub-rule (1) and (2) has been issued.
- (4) The Collector may for the purpose of enquiry—
 - (i) Look into corresponding rates as recommended by the District Level Committee and the rates approved by the Inspector General of stamps.
 - (ii) Call for any information or record from any public office, officer or authority under the Government or the Local Authority.
 - (iii) examine and record statement of any member of the public, officer or authority under the Government or the Local Authority;
 - (iv) inspect the property after due notice to the parties concerned.



लगातार.....5

(5) The Collector shall—

- (i) after considering the objections and representation received in writing from the person to whom notice under sub-rule (1) & (2) has been issued;
- (ii) after examining the records produced before him;
- (iii) after a careful consideration of all the relevant factors and evidence placed before him, and
- (iv) after consideration the corresponding rates as recommended by the DLC and the rates approved by the Inspector General of Stamps.

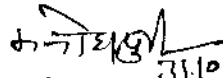
pass an order determining the market value of the property and duty payable on the instrument and take steps to collect the difference in the amount of stamp duty alongwith penalty, if any.

- (6) The summary enquiry shall be completed within a period of 3 months.
- (7) A copy of the order shall be forward to the Inspector General of stamps within 15 days from the date of order.

10. इस प्रकार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा ना तो मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(3) एवं ना ही राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना किया जाना पाया जाता है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित आदेश विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

8. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चारों निगरानियां स्वीकार करते हुए कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 28.12.2006 सपठित आदेश दिनांक 29.8.2007 अपास्त किये जाकर प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि उनके द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए, उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत निर्धारित की जाकर तदनुसार कमी मुद्रांक व पंजीयन शुल्क की देयता के विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किये जावें।

9. निर्णय सुनाया गया।


(मनोहर पुरी)
सदस्य